आमोखस व मिडिया की खबरों व प्रथम समाचार पत्र

RNI No. UPHIN/2012/47484

जननायक सम्राट

बर्ष :13 अंक :314 पृष्ठ -4 दिनांक 16 नबम्बर 2024 दिन शनिवार

वाराणसी में देव दीपावली देखने उमड़ेंगे लाखों श्रद्धालु, काशी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत पूरे शहर को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया

प्रयागराज – उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली पीसीएस और समीक्षा अधिकारी जैसी प्रमुख परीक्षाओं में बदलाव को लेकर तैयारी कर रहे छात्रों ने लोक सेवा आयोग पहुंचकर जमकर विरोध किया. इस दौरान लगभग 30 हजार की संख्या में प्रतियोगी छात्र पहुंच गए. हालांकि 11 नवंबर को महा धरना की पहले से ही आयोग को सूचना थी, जिसको लेकर इसके चारों ओर भारी बेरीकेडिंग कर दी गई थी. लेकिन छात्र इस वेरीकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए और गेट पर बैठकर धरना देने लगे.क्यों कर रहे वन शिफ्ट वन एग्जाम की मांग प्रतियोगी छात्रों ने लोकल 18 से बात करते हुए बताया कि पहले कभी भी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षा दो दिनों में नहीं आयोजित हुई है. आयोग के द्वारा या जानबूझकर नियमों में बदलाव किया जा रहा है. 2 दिन एग्जाम कराए जाने को लेकर छात्रों ने कहा कि इससे जहां परीक्षा की मौलिकता खत्म होगी वहीं प्रश्नों का सरल और कठिन होने में भी समस्या पैदा हो जाएगी. सम सामयिक विषय में कौन सा प्रश्न कठिन होगा, कौन सा सरल होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. उदाहरण के तौर पर पहले शिफ्ट में मराठों का संघर्ष पूछ ले और दूसरे शिफ्ट में मैसूर का युद्ध इस डटे रहे वहीं रात को भी जिलाधिकारी और कमिश्नर से भी इनकी बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला. छात्र हरेंद्र का कहना है कि सरकार युवाओं की भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है. इससे पहले 17 मार्च को पीसीएस की परीक्षा होनी थी, लेकिन समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक होने की वजह से इसे 24 अक्टूबर को होना था, लेकिन आयोग की ओर से परीक्षा के बीच में ही नियम में बदलाव किए जा रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है. हालांकि अभी आयोग की तरफ से कोई सूचना जारी नहीं हुई है. न ही द्विपक्षीय वार्ता में कुछ निष्कर्ष निकाल पाया है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार आशुतोष को जान से मारने की धमकी, पाकिस्तान से आया फोन

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे को जान से मारने और इलाहाबाद हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी है. आशुतोष पांडे के व्हाट्स वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उन्हें पाकिस्तान के आतंकी संगठन का नाम लेकर धमकी दी गई. पुलिस का कहना है कि इस मामले में उनकी ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में पक्षकार आशुतोष ने कहा कि उन्हें 13 नवंबर को व्हाट्सएप कॉल और वॉयस एसएमएस के जरिए पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन का नाम लेकर धमकियां दी गई हैं. जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है. उन्होंने कहा कि 19 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरी सुनवाई होनी है, उस सुनवाई में जाने पर मेरी हत्या करने, हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी और पीएम मोदी व गाय माता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है. पाकिस्तान के नंबर से दी गई धमकी उन्होंने कहा कि ये डर की बात नहीं है और न ही दहशत की बात है. ये सनातन का देश है और श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए हम अपनी जान क्या कुछ भी दे सकते हैं. हम पीछे नहीं हटेंगे, ऐसे आतंकी संगठनों की धमकियां पहले भी आई हैं और अब फिर से दे रहे हैं. हम किसी प्रकार से डरने वाले नहीं है. माननीय कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह हम जोरदार पैरवी करेंगे और श्री कृष्ण जन्मभूमि तो मुक्त करवाकर रहेंगे. वहीं इस पूरे मामले पर एसपी सिटी अरविंद कुमार ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर व्हाट्स एप के जरिए एक पोस्ट डाला है. जिसके माध्यम से ये पता चला है कि उन्हें धमकी दी गयी है. इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. ये हमें सोशल मीडिया से ही पता चला है. अगर वो कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं और तो इस मामले की जांच की जाएगी और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

मेरठ में करोड़ों रूपये के स्टांप घोटाले से हड़कंप, अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ खेल

उत्तर प्रदेश के मेरठ में करोड़ों रुपए के स्टांप घोटाले के मामला सामने आया है. घोटाले में अब तक 997 मुकदमे दर्ज किए जा चुके है. जिनको रजिस्ट्री विभाग द्वारा नोटिस भेजा जा चुका है. इन सभी मामलों में लोगों ने स्टांप अधिवक्ता विशाल वर्मा से लिए है जो इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है लेकिन विशाल और रजिस्ट्री विभाग के साजिशकर्ता अफसरों को बचाने की को. शिश की जा रही है. इस मामले में जहां रजिस्ट्री विभाग स्टांप लेने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रिकवरी करने में जुटा है तो वहीं इन लोगों का कहना है कि वो तो खुद धोखे का शिकार हुए हैं. हमने एक अधिवक्ता पर विश्वास करके स्टांप खरीदें और उसे रजिस्ट्री विभाग के अफसर ने उस समय मंजूर भी कर लिया. लेकिन, अब जांच हुई तो सभी स्टांप गलत पाए गए. इस मामले में ना तो अधिवक्ता विशाल वर्मा पर कार्रवाई हो रही है और न ही विभाग अपने अधिकारियों की जांच कर रहा है.

मेरठ में करोड़ों का स्टांप घोटाला इस मामले में पीड़ितों ने आरोपी अधिवक्ता विशाल वर्मा पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया है, एक शिकायतकर्ता खेल उत्पादों की कारोबारी ओम कुमारी ने बताया कि उन्होंने बीते कुछ सालों में अपनी प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के दस्तावेज रजिस्टर्ड कराएं थे. पड़ोस में रहने वाले वकील विशाल वर्मा को उन्होंने एकमुश्त लाखों रुपया दिया. इसके बाद रजि. स्ट्रियां हो गई. मई–2024 में उनके पास रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से स्टांप चोरी का एक नोटिस आया. पता किया तो मालूम चला कि उनकी एक रजिस्ट्री में एक लाख का स्टांप फर्जी लगा हुआ है. बताया जा रहा है कि वकील विशाल वर्मा बीते एक दशक में हजारों रजिस्ट्री में फर्जी स्टांप का इस्तेमाल करके अकूत संपत्ति कमाई है. बीते साल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में दो संदिग्ध स्टांप मिले थे. जांच हुई तो वो फर्जी पाए गए. इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया और बीते 3 साल की रजिस्ट्री में लगे स्टांप का वेरिफिकेशन हुआ. पता चला कि इस तरह की 997 रजिस्ट्रियां की गई है जो सभी विशाल वर्मा ने कराई हैं. आरोपी ने सभी स्टांप खरीदारों के नाम से खरीदे थे इसलिए रजिस्ट्रेशन विभाग ने 997 खरीदारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए हैं. इतने ही मुकदमे एआईजी स्टांप के कोर्ट में स्टांप चोरी के दायर किए गए हैं. ।प्ळ के यहां दर्ज मामलों में अब धीरे–धीरे स्टांप की रिकवरी की जा रही है. जिसका भुगतान खरीददारों को ही उठाना पड़ रहा है. मुकदमे दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

रुड़की मेंअनियंत्रित होकर पलटी बरातियों से भरी स्कॉर्पियो, दर्दनाक हादसे में 4 की मौत

दिल्ली–हरिद्वार हाईवे पर शुक्रवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से टक. राकर अनियंत्रित हो गई और पलट गई. इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. यह घटना उस समय हुई जब कार में सवार लोग मेरठ से रुड़की बारात में जा रहे थे. मेरठ से आठ लोग एक स्कॉर्पियो कार में सवार होकर रुड़की के चंद्रपुरी इलाके में हो रही शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे. जैसे ही गाड़ी देवबंद तिराहे के पास पहुंची, चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया. गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही थी अचानक चालक ने नियंत्रण को दिया और स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई. डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी कई बार पलटी खाकर सड़क पर बिखर गई. हादसे के बाद गाड़ी में सवार लोग चीख–पुकार करने लगे. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग और राहगीर घटनास्थल की ओर दौड़े और घायल लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की. इस हादसे में दो लोगों मुकुल और शेखर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया. इस सड़क हादसे में चार अन्य लोग घायल हो गए. जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है.हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे अन्य बाराती और परिवार के सदस्य इस दुर्घटना के बारे में बताते हुए शोक में डूब गए. एक घायल बाराती ने बताया कि वे सभी अलग–अलग गाड़ियों में मेरठ से रुड़की के लिए जा रहे थे और उनकी यात्रा शादी के समारोह में भाग लेने के लिए थी. उन्होंने यह भी बताया कि गाड़ी में सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे और हादसे में हुई मौतें परिवार के लिए एक बड़ा झटका हैं.

योगी के मंत्री के अकाउंटेंट से 2.08 करोड़ की ठगी नंदी के बेटे का फोटो . लगाकर किया था ये मैसेज

साइबर ठगों ने सूबे के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के अकाउंटेंट रितेश श्रीवास्तव से 2.08 करोड़ रुपये ठग लिए। व्हाट्सएप डीपी पर नंदी के बेटे की तस्वीर लगाए ठग ने मैसेज भेजा, मैं जरूरी बिजनेस मीटिंग में हूं। यह मेरा नया नंबर है, तुरंत पैसे भेजो। अकाउंटेंट ने तुरंत बताए तीन खातों में पैसे भेज दिए। भेद खुलने पर सनसनी मची। साइबर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। ठगी की यह वारदात बुधवार को हुई। मंत्री नंदी के अकाउंटेंट रितेश श्रीवास्तव के मोबाइल फोन पर अनजान नंबर से मैसेज आया। डीपी नंदी के बेटे की लगी हुई थी।मैसेज में लिखा था कि यह मेरा नया नंबर है। मैं एक बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग हूं। यह मीटिंग अभी काफी देर तक चलेगी। मुझे कुछ पैसों की तुरंत जरूरत है। इसके बाद साइबर ठगों ने बैंक खातों के तीन नंबर भेजे। कहा, पैसा तुरंत ट्रांसफर कर दो। मैसेज देखने के बाद अकाउंटेंट ने तीन बार में 2.08 करोड़ रुपये बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए। कुछ देर बाद रितेश को पता चला कि मंत्री के बेटे ने इस तरह का कोई मैसेज नहीं भेजा है और न ही अपने खाते में पैसा ही मंगवाया।इसके बाद प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक खलबली मची। ठगी की सूचना साइबर सेल थाना पुलिस को बुधवार रात करीब 11रू30 बजे दी गई। मामला कैबिनेट मंत्री से जुड़ा होने के कारण एक बारगी आला पुलिस अधिकारी भी सकते में आ गए। साइबर पुलिस रातभर जालसाजों के बैंक खातों का डिटेल खंगालने में जुटी रही।तीन खातों में ट्रांसफर हुआ पैसा साइबर पुलिस की जांच में पता चला कि जालसाज ने ठगी के लिए तीन बैंकों के खातों का इस्तेमाल किया है। इनमें आइ. सीआईसीआई, एचडीएफसी समेत एक अन्य बैंक का खाता शामिल है। साइबर पुलिस ने तीनों खातों की जानकारी बैंक अधिकारियों से मांगी है। साइबर थाना प्रभारी राजीव तिवारी ने बताया कि संबंधित खाते फ्रीज कराने के लिए मेल किया है। ठगों का ब्योरा खंगाल रहे हैं। वहीं, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता से अमर उजाला संवाददाता ने घटना के बारे में बात की कोशिश की, लेकिन उनके पीआरओ ने कहा कि अभी बात कराएंगे, पर यह हो नहीं सकी।

सैलानियों के लिए खुल गया राजाजी टाइगर रिजर्व, वन्य . कर्मियों ने तिलक लगाकर लोगों का किया स्वागत

प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर राजाजी टाइगर रिजर्व की पर्यटक रेंजों के द्वार शुक्रवार से सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं. मोतीचूर रेंज में सुबह करीब सात बजे वन्य जीव प्रतिपादक हरीश नेगी ने रिबन काटकर इस पर्यटन सीजन का उद्घाटन किया. उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली से आए 60 सदस्यीय दल का वन कर्मियों ने तिलक लगाकर और फूल–मालाओं से स्वागत किया. जिससे वहां मौजूद पर्यटकों और स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया. इस अवसर पर पर्यटकों के स्वागत के लिए गेट को आकर्षक ढंग से सजाया गया था.राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो अपनी वन्यजीव विविधता और समृद्ध जैविक विविधता के लिए प्रसिद्ध है. लगभग 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह रिजर्व हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिलों में स्थित है. राजाजी टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों और पक्षियों को करीब से देखने का अवसर मिलता है. हाथी,बाघ,गुलदार,चीतल, सांभर और मोर के अलावा कई ऐसे जीव–जंतु और पक्षी यहां देखने को मिलते हैं जो लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल हैं.हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राजाजी टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है. भारत के इस हिस्से में हाथियों की अच्छी संख्या है और उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं. इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में राजाजी में बाघों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे यह स्थान पर्यटकों के लिए और भी आकर्षक बन गया है. पार्क की चीला, मोतीचूर और हरिद्वार रेंज में सैलानी बाघों का दीदार कर सकते हैं. बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिकारियों ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से चार बाघों को राजाजी की मोतीचूर रेंज में शिफ्ट किया है, जिससे यहां बाघों की संख्या में और वृद्धि हुई है.पर्यटकों के लिए सफारी का आनंद राजाजी टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए जंगल सफारी की सुविधा उपलब्ध है जो उन्हें जंगल की गहराईयों में ले जाकर वन्यजीवों का नजदीकी अनुभव देती है. चीला और मोतीचूर रेंज में सफारी के माध्यम से पर्यटक बाघ, हाथी और अन्य वन्यजीवों को प्राकृतिक वातावरण में देख सकते हैं. पर्यटक इस सफारी के माध्यम से घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और शांत जल धाराओं के बीच जंगली जीवों को देख पाते हैं, जो उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव होता है. सफारी के दौरान पर्यटकों को प्रशिक्षित गाइड द्वारा जंगल के नियमों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करना होता है ताकि वन्यजीवों और पर्यटकों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम राजाजी टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को वन्य जीवों की विशाल विविधता के साथ–साथ प्रकृति का अद्वितीय सौंदर्य भी देखने को मिलता है.यहां का समृद्ध वनस्पति आवरण विभिन्न प्रकार के पक्षियों और जीवों का आश्रय स्थल है,जिनमें से कई लुप्तप्राय प्रजातियों में आते हैं. पर्यटकों को यहां भारतीय मोर, दुर्लभ पक्षी प्रजातियाँ, चित्तीदार हिरण, सांभर, और नीलगाय देखने का भी अवसर मिलता है. यह रिजर्व हिमालय की तलहटी में स्थित है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां, और शांत वातावरण सैलानियों को सुकून प्रदान करता है.

उप चुनाव पर असर डालेगी छात्र आंदोलन की आग

यूपी में नौ सीटों पर होने वाले विधानसभा उप चुनाव से पहले लोक सेवा आयोग के सामने नार्मलाइजेशन के विरोध में प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन की आग भले ठंडी की जा रही है, लेकिन इसकी सियासी आंच समीकरणों पर असर डाल सकती है। इस आंदोलन ने पूरे प्रदेश की राजनीति को तो प्रभावित किया ही है, हर वर्ग का ध्यान भी खींचा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह आंदोलन खत्म होकर भी नए सियासी गुल खिला सकता है। नार्मलाइजेशन के खिलाफ चार दिन से लोक सेवा आयोग के सामने दिन रात डटे रहने वाले प्रतियोगी छात्रों के आगे लोक सेवा आयोग बैकफुट पर आ गया है।उप चुनाव के बीच इस आंदोलन को लेकर जिस तरह विपक्ष हवा देने में जुटा था, उसे लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार के कान खड़े हो गए थे। कहा जा रहा है कि उप चुनाव के बीच गलत संदेश जाने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप कर आंदोलनकारी छात्रों को यह जताने की कोशिश की है कि सरकार उनके साथ है और प्रतियोगी छात्रों के हितों से किसी भी दशा में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। ाजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अभी आयोग ने पीसीएस प्री के सवाल पर प्रतियोगियोंयुवा की बात मानी है। आरओ , एआरओ को लेकर छात्र अभी भी आयोग के सामने डटे हुए हैं। ऐसे में अगर सरकार ने दिल बड़ा नहीं किया आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। ऐसे में यूपी की नौ सीटों पर हो रहे उप चुनाव पर इस आंदोलन का असर पड़ने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

दिल्ली के सराय काले खां चौक का बदला नाम

दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया. गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी. अब इस चौक को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा. केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चौक का नाम बदलने का ऐलान भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर शुक्रवार को किया.केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, ष्मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि सराय काले खान आईएसबीटी बस स्टैंड के बाहर बने चौक को अब भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा. इस प्रतिमा और उस चौक का नाम देखकर न केवल दिल्ली के नागरिक बल्कि अंत. र्राष्ट्रीय बस स्टैंड पर आने वाले लोग भी निश्चित रूप से उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे. ष्झारखंड में भगवान की तरह पूजे जाने वाले धरती आबा बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती है. देश उनकी जयंती पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहा है. बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची और आज के खूंटी जिले उलीहातू गांव में

एक आदिवासी परिवार में हुआ था. बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा था. उनकी मां का नाम करमी मुंडा था. भग. वान बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मिशनरी स्कूल में की थी. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने देखा की अंग्रेज भारतीयों पर जुल्म कर रहे हैं. इस जुल्म के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दिया. साल 1894 में जब छोटा नागपुर इलाके में अकाल और महामारी ने एक साथ दस्तक दी तो उस वक्त भी बिरसा मुंडा लोगों के हित में संघर्ष करते रहे. साल 1934 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ लगान माफी के लिए आंदोलन शुरू किया था. साल 1895 में भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया और हजारीबाग जेल भेज दिया गया. इसके बाद 1897 से 1900 के बीच अंग्रेजों और मुंडाओं के बीच युद्ध होते रहे.

ऑनलाइन 10 मिनट में सबसे ज्यादा क्या खरीदते हैं लोग, स्विगी के सीईओ ने किया खुलासा

नई दिल्ली. अमेजन–फ्लिपकार्ट जैसी ई–कॉमर्स कंपनियों से एक–दो दिन में सामान मंगाने के दिन अब लद गए. नया जमाना है क्विक कॉमर्स का, जो आपके ऑर्डर के 10 मिनट के भीतर सामान डिलीवर कर देते हैं. स्विगी का इंस्टामार्ट हो या जोमैटो का ब्लिंकिट, ये सभी कंपनियां 10 मिनट में सामान डिलीवर कर देती हैं. यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि लोग 10 मिनट में सबसे ज्यादा कौन सा सामान मंगाते हैं. स्विगी इंस्टामार्ट के सीईओ ने इसका खुलासा कर दिया है. आप भी इसे सुनकर अपना माथा पकड़ लेंगे.आए स्विगी इंस्टामार्ट के सीईओ श्रीहर्ष मजेटी ने बताया कि आपको क्या लगता है कि लोग 10 मिनट में कौन सी चीज सबसे ज्यादा मंगाना चाहते हैं. अगर मैं कहूं कि लोग इंस्टामार्ट पर सबसे ज्यादा बेडशीट ऑर्डर कर रहे हैं तो कौन यकीन करेगा. लेकिन, यह सच है हमारे प्लेटफॉर्म पर क्विक डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा बेडशीट ही ऑर्डर की जाती है. उन्होंने कहा कि पहले लोग बैटरी सबसे ज्यादा सर्च करते थे और अब बेडशीट का ऑर्डर बढ़ गया है.10 मिनट में डिलीवरी की मच गई है होड़ स्विगी के सीईओ ने कहा कि यह सुनकर भले ही अजीब लगे कि आखिर क्यों लोग 10 मिनट में बेडशीट की डिलीवरी चाहते हैं, लेकिन अगर यह मिल रहा है तो लोग अब खरीद भी रहे हैं. क्विक कॉमर्स और ई–कॉमर्स के बीच की रेखा अब समाप्त हो रही है. दूसरी ई–कॉमर्स कंपनियां भी अब जल्द डिलीवरी करने की तरफ बढ़ रही हैं. हमारी कंपनी हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन बाकी खिलाड़ी भी अब इस मैदान में कूद रहे हैं और क्विक डिलीवरी की होड़ सी मच गई है.सीईओ ने बताई सबसे बड़ी चुनौतीएक सीईओ के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है. इस पर मजेटी ने कहा कि कंपनी की शुरुआत करने के बाद से ही मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी को साथ लेकर चलने की थी. जैसे–जैसे आगे बढ़ते गए यह और मुश्किल होता गया, लेकिन लोगों को साथ लेकर चलना ही आज सफलता का राज बन गया है. यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जैसे–जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है, यही आधार बनता जाता है.चुनौतियों के बीच पैदा हुई स्विगी श्रीहर्ष ने बताया कि ऐसा नहीं है कि बाजार में सिर्फ स्विगी और जोमैटो ही प्रतिस्पर्धा में हैं. साल 2014 में जब स्विगी को शुरू किया गया था, तब बाजार में 19 से ज्यादा खिलाड़ी थे. आज क्विक कॉमर्स का बाजार बढ़कर 5.5 अरब डॉलर (करीब 50 हजार करोड़ रुपये) का पहुंच गया है. शुरुआत में इसे ग्रॉसरी आइटम की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो अब इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, स्पोर्ट उपकरणों तक पहुंच गया है.

महिला आयोग की सदस्य का बड़ा बयान, कहा– खनन माफिया को मिट्टी में मिला देंगे

खनन अधिकारी से छेड़छाड़ मामले पर राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. प्रियंका मौर्या ने कहा कि प्रदेश में योगी जी की सरकार है। हम खनन माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ प्रियंका मौर्या शुक्रवार को अचानक जिला महिला अस्पताल पहुच गईं। उन्होंने निरीक्षण किया और साफ सफाई व्यवस्था की खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिये। इस दौरान महिला खनन अधिकारी से छेड़छाड़ के मामले में एक बड़ा बयान दिया।कहा कि यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ऐसे माफिया को निश्चित रूप से मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा।उन्होंने कहा कि खनन अधिकारी की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों से बात हुई है। उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। देर से एफआईआर दर्ज होने के सवाल पर बोलीं कि महिला खनन अधिकारी घटना के नाद सहम गई थीं।वह उच्चाधिकारियों से बात करके कार्रवाई करवाना चाहती थीं। जैसे ही उन्होंने घटना रिपोर्ट की, वैसे ही तीन आरोपी पकड़े गए।

मैडम.ब्लैकमेलिंग करने वालों से बचाइए

सीतापुर। मैडम...जिले में एक महिला झूठे आरोपों में कई लोगों को फंसाकर ब्लै. कमेल करने का प्रयास करती है। मेरे ऊपर भी दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाया था। जांच में पुलिस ने क्लीन चिट दी। कृपया ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें।कोतवाली देहात के भग. वानपुर गांव निवासी पंकज अवस्थी अपनी पीड़ा सुनाते हुए फफक पड़े। बृहस्पतिवार को तहसील सदर के सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. प्रियंका मौर्या जनसुनवाई कर रही थीं। पंकज की पीड़ा सुनकर उन्होंने जांच का आश्वासन दिया। पंकज की तरह ही अन्य फरियादियों ने भी अपनी पीड़ा बयां की। इस दौरान कुल 43 प्रकरण आए। इस दौरान सीओ सिटी अमन सिंह, जिला प्रो. बेशन अधिकारी प्रिया पटेल व अन्य अफसर मौजूद रहे।जिला कारागार का किया निरीक्षण महिला आयोग की सदस्य ने जिला कारागार का भी निरीक्षण किया। इस दौरान महिला बैरक में निरुद्ध महिला बंदियों से संवाद किया। महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों की सुविधाओं पर चर्चा की। खैराबाद ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों का अन. नप्राशन संस्कार किया। महिलाओं का गोद भराई कार्यक्रम संपन्न कराया।

नगर निगम की गाड़ी ने ई–रिक्शा में मारी टक्कर, नाले में उछलकर गिरी बच्ची, हुई मौत

अलीगढ़ में थाना बन्नादेवी क्षेत्र के गांव एलमपुर गड़िया के पास 14 नवंबर शाम नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी ने ई– रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा में परिजनों के साथ सवार डेढ़ साल की बच्ची उछलकर सड़क के बगल में नाले में जा गिरी। पानी में डूब जाने से उसकी मौत हो गई। जबकि हादसे में ई– रिक्शा चालक उसकी पत्नी और चाची घायल हो गईं। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घने कोहरे में लिपटी सुबह, गुलाबी जाड़े ने दी दस्तक

एटा। जिले में बृहस्पतिवार सुबह घने कोहरे में लिपटी रही। कम दृश्यता के कारण वाहनों की रफ्तार भी धीमी रही। इसके साथ ही गुलाबी जाड़े ने दस्तक दे दी। कोहरे की वजह से सूर्यदेव सुबह करीब 10 बजे चमके और धूप भी हल्की रही। अगले तीन दिन मौसम कुछ इसी तरह का रहेगा।बुधवार की सुबह भी को. हरा था, लेकिन हल्का रहा था। जबकि बृहस्पतिवार की सुबह जब लोग सोकर उठे और बाहर निकले तो कोहरा देखकर चौंक गए। करीब 50 मीटर की दूरी के बाद दिखाई देना मुश्किल था। साथ ही मौसम में भी ठंडक बढ़ी हुई महसूस हुई। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि बुधवार तक यह 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा था। कोहरे की वजह से सबसे बड़ी समस्या यातायात संचालन में हुई। वाहनों को लेकर जो लोग निकले थे, दृश्यता कम होने की वजह से ढंग से नहीं चल पा रहे थे। काफी हल्की रफ्तार में बढ़ रहे थे। ऐसे में सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे थे।कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसके सिंह ने बताया कि मौसम में बदलाव आ रहा है। आने वाले दिनों में और तेजी से बदलेगा। अगले तीन दिन सुबह के समय कोहरा पड़ेगा। साथ ही तापमान में भी कमी आएगी।

जीजा से हुआ प्यार बीमार बहन की . देखभाल करते–करते दे बैठी दिल,

मैनपुरी में जीजा और साली के प्यार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बीमार बहन को देखने आई युवती को जीजा से प्यार हो गया। दोनों के बीच संबंध बन गए। अब वो गर्भवती हो गई है, जिसके बाद जीजा के साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई है। मैनपुरी के बेवर में बहन के बीमार होने की खबर मिलने के बाद देखभाल करने आई युवती को जीजा से प्यार हो गया। दोनों के बीच विवाहेत्तर संबंध बने और अब युवती गर्भवती हो चुकी है। वह अब जीजा के साथ रहने की जिद पर अड़ी है। पुलिस ने दोनों बहनों के न्यायालय मे बयान दर्ज कराए हैं।गर्भवती हो गई युवती थाना क्षेत्र के एक गांव में निवासी युवती छह माह पूर्व अपनी बहन की ससुराल बीमार बहन की देखभाल करने के लिए आई थी। बहन की ससुराल में रहने के दौरान युवती को जीजा से प्रेम हो गया। दोनों के बीच संबंध भी बन गए। अब युवती ने जीजा के साथ ही रहने की जिद ठान ली है और विरोध करने पर चौंकाने वाला खुलासा करते हुए खुद को गर्भवती बताया है। उधर पत्नी को जब इस बारे में पता चला कि होश उड़ गए। पति की बेवफाई और बहन कि बेतुकी मांग के आगे बहन खुद को असहज महसूस कर रही है।

मशीन में फंसकर कट गया मजदूर का हाथ, तड़प–तड़प कर गई जान

आगरा में प्लास्टिक का पाइप बनाने वाली फैक्टरी में काम करते समय मजदूर का हाथ मशीन में फंस गया। उसे जब तक बचाया जाता, तब तक हाथ कट गया और उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र के नुनिहाई स्तिथ पाइप बनाने वाली अतुल फैक्टरी में शुक्रवार को काम करते वक्त एक मजदूर का हाथ मशीन की बेल्ट में जाने से कटकर अलग हो गया। मौके पर काम कर रहे फैक्टरी में अन्य कर्मच. ारियों ने जब चीखने की आवाज सुनी तब मशीन को बंद करवा कर इलाज के लिए भेजा गया। जहां इलाज के दौरान मजदूर की मौत हो गई।टूंडला के नगला झम्मन निवासी 50 वर्षीय राजेन्द्र का काम करने के दौरान अचानक हाथ मशीन की बेल्ट में फंस गया। हाथ कटकर अलग हो गया। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आरोप है कि फैक्टी में न एम्बुलेंस और न ही अन्य आपात सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिस कारण घायल राजेन्द्र को लोडिंग टैम्पो से अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया है। जहां उसकी मौत हो गई। थाना एत्माद्दौला प्रभारी राजेन्द्र त्यागी ने बताया कि मशीन की चपेट में हाथ आ जाने के कारण कटकर अलग हो गया था। परिजनों को घटना की सूचना दे दी

गूंज रहे हर–हर गंगे के जयकारे, दीपों की रोशनी से जगमग हुई गंगा मैया.

अनूपशहर नरौरा। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान का मेला गुलजार हो गया। तंबुओं के शहर में उत्साह देखा गया तो मेले में सजी दुकानों पर भीड़ लगी देखी गई। वहीं, पूरा दिन हर–हर गंगे के जयकारों की गूंज रही। बृहस्पतिवार शाम के समय दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धालुओं ने दीपदान किया तो गंगा मैया रोशनी से जगमग हो उठी। मुख्य स्नान शुक्रवार को है तो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है।गंगा के घाट और रेती में करीब पांच किलोमीटर के दायरे में मेला पिछले कई दिन से गुजार होने लगा था। 12 नवंबर को विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ 15 दिवसीय मेले का उद्‌घाटन हुआ। इसी के साथ मेले में व्यापक सुविधाएं की गई। गंगा की रेती में मेले स्थल पर बृहस्पतिवार दिनभर श्रद्धालुओं का जत्था गंगा तट पर पहुंचता रहा। वहीं, बृहस्पतिवार की शाम होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पितरों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान किया। इससे गंगा जगमगा गईं। आधी रात से हर–हर गंगे के उद्‌घोष के साथ पूर्णिमा का स्नान शुरू हो गया। करीब चार लाख से अधिक श्रद्धालुओं के गंगा में डुबकी लगाने का अनुमान है। मुख्य स्नान क्षेत्र अनूपशहर में गंगापुल रेती को बनाया गया है। इसके साथ ही बबस्टरगंज गंगा रेती व मस्तराम घाट पर स्नान के इंतजाम किए गए हैं। गंगा पुल रेती में याकूबपुर, सलेमपुर, दूसरी, चित्सोन, मांगरौल गांवों तथा दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों से अपनी गाड़ियों, बैलगाड़ियों व ट्रैक्टर ट्रॉली से आए श्रद्धालुओं ने तंबू लगाकर बसेरा डाल रखा है।वहीं, दूसरी ओर जिला प्रशासन और नगर पालिका की ओर से मेला परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए साफ सफाई, शौचालय, चिकित्सा, पशुचिकित्सा व पेयजल आदि की व्यवस्था की गई है। दिनभर युवा श्रद्धालु गंगा की रेती में मस्ती करते नजर आए। महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चूल्हे पर खाना बनाती दिखीं। पुरुष ताश खेलकर व हुक्का गुड़गुड़ाकर अपना मनोरंजन कर रहे हैं। कहीं बैल दौड़ तो कहीं ट्रैक्टर दौड़ हो रही है। –

मेले में दुकानें भी सज गई हैं। मीना बाजार, कपड़े, खाने पीने की वस्तुओं के साथ घरेलू वस्तुओं की भी दुकानें सज गई हैं। वहीं, दूसरी ओर बबस्टर गंज स्थित कांती प्रकाश सरस्वती शिशु मंदिर में मुख्य मेला कंट्रोल रूम व मेला कोतवाली बनाया गया है। इसके साथ ही पांच किलोमीटर के दायरे में लगे मेले की ड्रोन, सीसीटीवी व वॉच टॉवर से निगरानी रखी जा रही है। नगर पालिका परिषद कार्यालय में खोया पाया केंद्र बनाया गया है तथा सीसीटीवी कैमरों से बबस्टर गंज से अंबेडकर पार्क तक के क्षेत्र में निगरानी की जा रही है।अहार और नरौरा समेत सभी घाटों पर भी मेला हुए गुलजार अहार और नरौरा समेत जिले के सभी गंगा घाटों पर भी मेला गुलजार हो गए। इन घाटों पर क्षेत्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। बता दें कि अहार में आसपास क्षेत्र के गांव के अलावा बाहर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान को पहुंचते हैं। यहां पर सिद्धबाबा घाट और मां अवंतिका देवी घाट पर गंगा स्नान की व्यवस्था की गई है। इसी तरह नरौरा के रामघाट और राजघाट में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। यहां पर भी मेला व दुकान सज गई हैं और श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। इन सभी गंगा घाटों पर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

फिरोजाबाद में गैंगस्टर की 86 लाख की संपत्ती कुर्क

फिरोजाबाद के एका में गैंगस्टर कार्रवाई के तहत अभिक्तों की 86 लाख की संपत्ती कुर्क की गई। जसराना के उप जिलाधिकारी और थाना एका पुलिस ने मुनादी कराई, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की गई।

अजित पवार की बात सुन कूदे राहुल गांधी, घिर गई शिंदे सरकार

महाराष्ट्र में सियासत खूब गर्म रहती है। चुनाव के दौरान भी चुनाव के बाद भी। लेकिन अब ऐसा हुआ है जिससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र में फिर कुछ उलट पलट सकता है।चुनाव से पहले अडानी को लेकर सियासत गरमा गई है।

खैर पहुंचे अखिलेश यादव, बोले–भाजपा को डीएपी में नजर आ रहे है पीडीए

खैर(जननायक सम्राट) उपचुनाव के अंतर्गत समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी चारु कैन के लिए यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं।यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव लगभग डेढ़ घंटे की देरी से अलीगढ़ के खैर में पहुंच गए हैं। मंच पर अखिलेश यादव का सपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर ने अपने उद्बोधन से स्वागत किया। सपा प्रत्याशी चारु केन ने कहा कि यह देश किसानों का है, पूंजीपतियों का नहीं है। आखिर कब तक हम भाजपा के जुमलों में फंसे रहेंगे। इस उपचुनाव में विकास और अपने स्वाभिमान के लिए वोट कीजिए। जैसे तेजवीर सिंह गुड्डू ने जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए सभी गांव का विकास कराया, मैं भी आपकी सेवा में रत रहूंगी। अखिलेश यादव को चारु केन ने भावी मुख्यमंत्री कहा।अखिलेश यादव ने कहा यह जनसभा को संबोधित करते हुए

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को जैसे ही भनक पड़ी, उन्होंने चुनाव की तारीख ही बदल दी। यहां आने से पहले सीएम योगी को सुन रहा था, वह क्या–क्या कह रहे हैं। भाजपा को डीएपी में भी पीडीए नजर आ रहा है। न पीडीए को कुछ दिया है और न किसानों को कुछ दिया है। वहीं डीएपी पहुंचा रहे हैं, जहां चुनाव हैं। जो कहते थे किसान की आय दो गुनी कर देंगे, वह किसान को डीएपी, बीज भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। बिजली, खाने का सामान, पेट्रोल–डीजल मंहगा है।
सोने की कीमत कहां पहुंचा दी है। 2014 में सोने से लेकर और की कीमत क्या थी, अब क्या। बीजेपी के लोग अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौज की भर्ती भी देखिए कैसे हो रही है। जब समा. जवादियों को मौका मिलेगा अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। बजट कितना भी खर्च हो जाए पक्की नौकरी और पक्की वर्दी उपलब्ध कराएंगे। नौजवान तभी धरने से हटेगा, जब उसकी पूरी मांगे पूरी होंगी। किसान नाराज होने पर सरकार को काले कानून वापस लेने पड़े। हमारे समय किसान ने कभी आंदोलन नहीं किया।
यही अलीगढ़ है, यही टप्पल है, जहां सपा ने साइकिल चलाई थी। जब सपा ने किसान नेता तेवतिया को झूठे मामले से निकाला। यह हमारे मुख्यमंत्री पीडीए की जो परिभाषा दे रहे हैं वह डीएपी की परिभाषा नहीं जानते। हरदुआगंज तापीय परियोजना सपा की ही देन है, पर किसान की बिजली सस्ती नहीं हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी पावर हाऊस का नाम नहीं ले रहे।

बाइक पर जा रहे दो युवकों में वाहन ने मारी .टक्कर, एक की हुई मौत और दूसरा गंभीर घायल

हाथरस गांव नगला बिहारी निवासी विकास व विनोद बाइक पर सिकंदराराऊ से वापस अपने गांव जा रहे थे। गांव चमरोली के पास बाइक में किसी वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से विनोद की मौके पर ही मौत हो गई।14 नवंबर की रात्रि 9 बजे हाथरस रोड पर गांव चमरोली के पास बाइक पर जा रहे दो युवकों में वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर घायल हो गया। घायल का अलीगढ़ में उपचार चल रहा हैं।प्राप्त जानकारी के अनुसार हाथरस रोड के गांव नगला बिहारी निवासी 25 वर्षीय विकास पुत्र रामेश्वर व विनोद पुत्र उदयवीर रात्रि 9 बजे बाइक पर सिकंदराराऊ से वापस अपने गांव जा रहे थे। गांव चमरोली के पास बाइक में किसी वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। विकास गंभीर रूप से घायल हो गया। विकास को सीएचसी से अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद टक्कर मारने वाला चालक वाहन लेकर वहां से भाग गया। पुलिस ने विनोद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

जज को घेरने वाले बदमाश कौन, घटना पर सब मौन, फिर खुलासा करेगा कौन

पुलिस टीमों ने हाईवे पर खेरेश्वर चौराहे से लेकर टप्पल इंटरचेंज तक 230 सीसीटीवी कैमरे चेक किए हैं। 100 लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ भी की है। जज ने मुकदमे में जिस बोलेरो का जिक्र किया है उसका नंबर ही फर्जी निकला।फर्रुखाबाद के न्यायाधीश डॉ. अनिल कुमार को हाईवे पर घेरने वाले बदमाशों का सुराग पुलिस पांच दिन बाद भी नहीं लगा सकी है। सफेद रंग की बोलेरो किसकी थी। कहां की थी इस सवाल का जवाब भी फिलहाल थानाध्यक्ष से लेकर पुलिस के आला अफसरों तक पर नहीं है। जबकि पुलिस का दावा है कि अब तक 230 कैमरे चेक किए जा चुके हैं।100 लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ की जा चुकी है। अफसर बार–बार एक ही जवाब देते हैं कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में सफेद रंग की कोई बोलेरे अभी तक नहीं दिखी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि न्यायाधीश ने जिस सफेद रंग की बोलेरो का उल्लेख रिपोर्ट में किया है, वह गई तो गई कहां।खैर कोतवाली में 9 नवंबर को दर्ज कराए गए मुकदमे के बाद एसएसपी संजीव सुमन ने घटना का खुलासा करने के लिए चार टीमों का गठन किया था। एसओजी, क्राइम ब्रांच के साथ ही खैर कोतवाली की दो टीमों को लगाया गया। इन टीमों ने हाईवे पर खेरेश्वर चौराहे से लेकर टप्पल इंटरचेंज तक 230 सीसीटीवी कैमरे चेक किए हैं। 100 लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ भी की है। जज ने मुकदमे में जिस बोलेरो का जिक्र किया है उसका नंबर ही फर्जी निकला। नंबर के आधार पर बोलेरो अलीगढ़ की मानी जा रही थी। अब अलीगढ़ आरटीओ में पंजीकृत सभी 4095 बोलेरो की लोकेशन तलाशी जा रही है। मुकदमे में जांच लगातार जारी है। अभी तक पूरी जांच में कहीं भी साफ नहीं हुआ है कि घटना में प्रयुक्त की गई बोलेरो अलीगढ़ नंबर की है। आरटीओ कार्यालय से भी पुष्टि कर ली गई है। फिर भी मामले में गहनता से जांच जारी है।– डीके सिसोदिया, प्रभारी निरीक्षक खैर रिपोर्ट के आधार पर मामले में गहनता से जांच की जा रही है। इसमें क्राइम ब्रांच, एसओजी व कोतवाली थाने की दो टीमें जांच में जुटी है। अभी तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। विवेचना जारी है।– वरुण कुमार सिंह, सीओ खैर विशेष न्यायाधीश की गाड़ी को ओवरटेक करने व धमकाने के मामले में करीब 230 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया है। कहीं भी विशेष न्यायाधीश की गाड़ी के आस–पास या पीछे कोई भी गाड़ी पीछा करते हुए दिखाई नहीं पड़ी है। 100 से अधिक स्थानीय लोगों से भी घटना के बारे में जानकारी ली गई है। किसी ने भी घटना के बारे में कुछ भी नहीं देखा है और न ही कोई संदिग्ध कार पीछा करते हुए मिली है।– मुकेश चंद्र उत्तम, एसपी देहात

29 अक्तूबर की थी घटना...पुलिस ने 9 नवंबर को दर्ज किया था मुकदमा
नोएडा जाते वक्त न्यायाधीश के साथ घटना 29 अक्तूबर को हुई थी। जज ने घटना की जानकारी तत्काल उसी वक्त एसएसपी के पीआरओ और सोफा पुलिस चौकी इंचार्ज को दी थी लेकिन फिर भी पुलिस सक्रिय नहीं हुई। होना तो यह चाहिए था कि मौखिक जानकारी को ही प्रथम सूचना मान, उसी वक्त मुकदमा दर्ज कर पुलिस पड़ताल करती। लेकिन जब नौ नवंबर को न्यायाधीश ने घटना के संबंध में तहरीर भेजी और ईमेल किया तब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कुल मिलाकर घटना के 12 दिन बाद पुलिस सक्रिय हुई।

सुंदर भाटी गिरोह पर हमले की कोशिश का जताया था अंदेशा
कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी के गिरोह पर हमले की कोशिश करने का अंदेशा जताया गया है। कहा गया कि 2021 में न्यायाधीश ने इस गिरोह के सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसका बदला लेने के लिए गिरोह ने उन पर हमले की कोशिश की। एक संभावना उन्होंने रोडरेज की भी जताई थी।

यूपी के अलीगढ़ में टप्पल से यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे और धुंध के कारण हादसों . भारी वाहनों की रफ्तार को कम करने का फैसला किया है.

अलीगढ़ यूपी में अलीगढ़ के टप्पल से यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे और धुंध के कारण हादसों में इजाफा होने लगता है. इसे रोकने के लिए यमुना प्राधिकरण ने 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक हल्के और भारी वाहनों की रफ्तार को कम करने का फैसला किया है. जहां हल्के वाहनों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है. जबकि भारी वाहनों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है. निर्धारित गति से अधिक होने पर वाहनों के चालान किए जाएंगे.कोहरे में होते हैं अधिक सड़क हादसेआपको बता दें कि कोहरे में सर्वाधिक हादसे होते हैं. इसे लेकर प्रशासन ने पहले से ही प्लान तैयार कर लिया है. सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे. ट्रालियों पर रिफ्लेक्टर लगाने की तैयारी शुरू होने जा रही है. इसे लेकर अलीगढ़ आरटीओ प्रशासन दीपक शाह ने बताया कि कोहरे के दौरान रफ्तार पर लगाम लगाने एवं हादसा रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर गति सीमा घटा दी है. यह बदला हर साल नवंबर माह में किया जाता है.

इसी प्रकार इस साल भी किया गया है. हाईवे पर भी वाहनों की स्पीड पर रहेगी नजरआरटीओ प्रशासन दीपक शाह ने कहा कि सभी हाईवे पर भी वाहनों की रफ्तार पर नजर रहेगी.
अलीगढ़–गाजियाबाद हाईवे,
अलीगढ़–कानपुर हाईवे,
अलीगढ़–मुरादाबाद हाईवे, अलीगढ़–टप्पल मार्ग, अलीगढ़–मथुरा मार्ग पर अधिक रफ्तार से दौड़ने वाले वाहनों के चालान किए जाएंगे. हाईवे पर लगे कैम. रों से स्पीड चेक की जाएगी. कैमरे द्वारा हाई स्पीड होने पर तत्काल चालान भी काटे जाएंगे.अलीगढ़ एसपी ट्रैफिक ने बताया वहीं, अलीगढ़ एसपी ट्रैफिक मुक. `श चंद्र उत्तम ने बताया कि सभी चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद रहेगी. वाहन चालकों को जागरूक भी किया जाएगा, जिससे हादसों को होने से रोका जा सके. उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि कोहरे की स्थिति में वाहनों की तेज गति एक्सीडेंट का सबक बनती है. ऐसे हादसों को रोकने के लिए ही यह कदम उठाए जा रहे हैं.

अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन, हाइवे पर लगाया जाम, गाजियाबाद के जिला जज के पुतले का किया दहन

अलीगढ़ के अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और बाद में अलीगढ़–मुरादाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया। अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद के जिला जज के पुतले का भी दहन किया।गाजियाबाद में अधिवक्ताओं के साथ हुई मारपीट के विरोध में अलीगढ़ के अधिवक्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने हाईवे पर जाम भी लगा दिया, जिससे वाहनों की कतार लग गई।गाजियाबाद प्रकरण को लेकर अधिवक्ताओं की हड़ताल और आंदोलन लगातार जारी है। इस क्रम में अधिवक्ताओं ने 15 नवंबर को पहले जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और बाद में अलीगढ़–मुरादाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद के जिला जज के पुतले का भी दहन किया।

मैं बृजेश कुमार चौहान गांव भोगपुर पोस्ट भगतपुर जिला ब्लॉक चंदौस जिला अलीगढ़ का निवासी हूं एवं जल शक्ति मंत्रालय से सेवानिवृत हू मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन को बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत भोगपुर भगतपुर ब्लॉक चंदौस अलीगढ़ में मन. रेगा की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है खंड विकास अधिकारी चंदौस RTI/ स्थापना/RTI 2024 दिनांक 30/04/2024 मैं कहते हैं ग्राम सभा भोगपुर भगतपुर में वित्तीय वर्ष 23–24 के अंतर्गत मनरेगा योजना से कुल 41 कार्य कराए गए हैं जिसके सापेक्ष 42.08 लाख रुपए खर्च किए गए हैं वही खंड विकास अधिकारी पत्रांक धशिवओव प्लैत्ध्2024 दिनांक20ध्08ध्2024 को प्रभारी अधिकारी शिकायत कलेक्ट्रेट कमरा नंबर 38 अलीगढ़ को सूचना देते हैं कि बृजेश कुमार पुत्र तोता सिंह द्वारा वित्त वर्ष 23– 24 में 41 कार्य के सापेक्ष जो 42 लाख का भुगतान होना बताया गया है वह इतना न होकर 35 कामों पर 24 लाख का भुगतान है

जब कि इनको कभी 42 लाख का भुगतान होना मैंने नहीं बताया है यह लेटर दोनों खंड विकास अधिकारी चांडोस अलीगढ़ की रिपोर्ट बता रही है मैंने इसकी शिकायत सचिव महोदय ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली श्री योगीआदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार निदेशक सतर्कता सतर्कता मुख्यालय लखनऊ मंडली आयुक्त अलीगढ़ को शिकायत भेज चुका हूं तथा आपसे अनुरोध करता हूं कार्रवाई करने में सहयोग प्रदान करें जिन्होंने एक दूसरे के साथ मिली भगत करके मनरेगा योजना के तहत जारी सरकारी धन का गवन किया अब उक्त खंड विकास अधिकारी चंदौस ने अपने सहयोगियों को बचाने के लिए त्ज्ञ आवेदन के उत्तर में जानबूझकर गलत जानकारी प्रदान की है अर्हे खंड विकास अधिकारी चंदौस अलीगढ़ ने दिनांक 20. 8.2024 के उत्तर में जीरोधा भाषी जानक. ारी दी है कि वित्त वर्ष 2023– 24 में विरोधाभासी जानकारी दी है कि 2023 24 में ग्राम कि आप खंड विकास अधिकारी चंदौस तथा ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव ग्राम पंचायत भोगपुर भगतपुर जिला अलीगढ़ के खिलाफ उचित आपराधिक और आ गया पंचायत भोगपुर भगतपुर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में कुल 35 कार्य किए गए हैं उन पर 24 लाख खर्च किए गए हैं जोकि आरटीआई उत्तर दिनांक 30 4.24 के विरोधाभासी है 20.8.2024 एवं 30.4.2024 का पत्र देखने योग्य है

अलीगढ़ के जिला महिला अस्पताल में मारपीट, फायरिंग करने पर मुकदमा दर्ज, दो गिरफ्तार

अलीगढ़ के मोहनलाल गौतम महिला जिला अस्पताल में 14 नवंबर की देर रात बच्चे का उपचार कराने आए तीमारदारों ने स्टाफ के साथ मारपीट की। गार्ड को दूसरी मंजिल से नीचे फेंकने का प्रयास किया। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी वहां से भाग गए। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना बन्ना देवी अंतर्गत मोहनलाल गौतम महिला जिला अस्पताल में देर रात तीमारदार एक बच्चे को लेकर पहुंचे। वहां पर उपचार कराने की जिद पर अड़ गए। वहां मौजूद गार्ड ने बच्चे को सामने मलखान सिंह जिला अस्पताल में उपचार कराने की सलाह दी। जिस पर तीमारदार भड़क गए और अन्य लोगों को भी वहां बुला लिया। बच्चे को उपचार कराने आए तीमारदार और अन्य ने गार्ड के साथ मारपीट की और उसे दूसरी मंजिल की ओर खींच कर ले गए। दूसरी मंजिल से गार्ड को नीचे फेंकने का प्रयास किया। गार्ड को बचाने पहुंची महिला स्टाफ को भी लोगों ने धक्का मार दिया। बताया जा रहा है कि लोगों ने अस्पताल परिसर में फायरिंग भी की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल परिसर में पहुंची। वहां पर पुलिस को आता देख मारपीट करने वाले आरोपी वहां से भाग गए। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। मुकदमा दर्ज, दो आरोपी दबोचे क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय ने बताया कि मामले में गार्ड नरेंद्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य अभियुक्त दिशांशु और सह अभियुक्त आयुष को असलाह समेत गिरफ्तार कर लिया गया है।

एएमयू छात्रसंघ का मुद्दा पहुंचा हाईकोर्ट

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव का मुद्दा अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में एएमयू के विधि संकाय के छात्र की ओर से एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है, जिस पर सुनवाई के लिए 18 नवंबर तारीख नियत की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विधि विभाग से एलएलएम कर रहे छात्र क़ैफ हसन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की है। जिसमें एएमयू प्रशासन द्वारा छात्र संघ चुनाव कराने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने लिंगदोह सिफारिशों के हवाले से एएमयू प्रशासन द्वारा त्वरित मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति और छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने 2019 से लगातार 6 साल तक छात्र संघ चुनाव न कराने की अवस्था में छात्र संघ निधि का ब्यौरा भी तलब किया है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अली बिन स़ैफ कर रहे हैं। जिसमें सुनवाई के लिए तारीख नियत कर दी गई है।

अडानी सेठ का क्या करें?

अजीत पवार और एकनाथ शिंदे कितना भी शौर्य का और स्वाभिमानी होने का दिखावा करें, लेकिन वे मोदी–शाह के गुलाम हैं। ये सब बंदर हैं और इनके मदारी वहां गुजरात में बैठे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अडानी पर अपने बयान को लेकर अजीत पवार २४ घंटे के भीतर 'यू–टर्न' नहीं लेते यानी पलटी नहीं मारते। पवार ने खुलासा किया था कि सरकार गिराने के खेल को लेकर जो बैठक हुई थी, उसमें फडणवीस और अन्य लोगों के साथ अडानी सेठ खुद मौजूद थे, इससे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति पर मोदी–शाह और अडानी की वैहसी पकड़ है, लेकिन अगले २४ घंटे में अजीत पवार पलट गए और अपने बयान से अडानी सेठ का नाम हटा दिया। अब अजीत पवार कह रहे हैं, 'अडानी सेठ उस बैठक में मौजूद नहीं थे।' यह दिल्ली–गुजरात में भाजपा की सेठ मंडली के डंडे का कमाल है कि अजीत पवार को पीछे हटना पड़ा। अजीत पवार हमेशा अपने भाषणों में कहते हैं, 'मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मैं हमेशा सच बोलता हूं।' लेकिन अजीत पवार की मौजूदा हालत और चेहरे को देखते हुए ये बात सच नहीं लगती। शिंदे–अजीत पवार के मदारी डमरू बजाते हैं और उनके हुक्म पर ये नाचते–कूदते हैं। महाराष्ट्र की जनता ये देख रही है। भाजपा की राजनीति पैसे वालों की राजनीति है। जो हमारे विचारों के नहीं हैं उन्हें हम पैसों के बल पर खरीद सकते हैं उनका यह गुरुर महाराष्ट्र को रसातल में डालता दिखाई दे रहा है। शिंदे और अजीत पवार ने दावा किया था कि उन्हें अपने ऊंचे आदर्शों के कारण अपनी–अपनी पार्टियां छोड़नी पड़ीं। शिंदे ने कहा, 'यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व से अलग हो जाएं।' लेकिन क्या गौतम अडानी उनके नए हिंदूहृदयसम्राट हैं? या फिर इन्हीं धनाढ्य हिंदू सम्राटों के मार्गदर्शन में बैठकें कर शिवसेना को तोड़ने और महाराष्ट्र की सरकार को उखाड़ फेंकने के पैहसले किए गए? राज्य में अडानी, लोढ़ा, आशर आदि बिल्डरों और उद्योगपतियों की दलाली करनेवाली सरकार सत्ता में बैठा दी गई है। अजीत पवार ने कह दिया कि महाराष्ट्र सरकार की चाबी अडानी सेठ के हाथ में है। भले ही वे बाद में मुकर गए, लेकिन उन्होंने जो कहा वही सच है। उद्योगपति राज्य के दुश्मन नहीं होते, लेकिन अडानी सेठ जैसे उद्योगपति महाराष्ट्र को ही निगलने पर तुले हैं और इसके लिए उन्हें ऐसी सरकार की जरूरत है जो उनके हुक्म का पालन करें। उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के लिए विधायकों को पचास–पचास करोड़ रुपए दिए गए थे। अजीत पवार के खुलासे से पता चला कि ये सारा पैसा किसने मुहैया कराया! ठाकरे सरकार को गिराने के लिए करीब दो हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए और इसका बड़ा भार अडानी सेठ ने उठाया। तो इस खर्च की भरपाई वैहसे करें? सेठजी बिजनेस करते हैं। उन्होंने चौरिटी शुरू नहीं की है। उनका हिसाब है कि अगर रुपया लगाया जाए तो बदले में पांच हजार मिलने चाहिए इसलिए अडानी सेठ ने महाराष्ट्र में सरकार को गिराने के लिए जो दो हजार करोड़ रुपए लगाए उसके बदले में कम से कम डेढ़ लाख करोड़ रुपए मिलेंगे और मुंबई की सारी जमीनें उनकी जेब में डाल दी गयी हैं। धारावी पुनर्वास सबसे बड़ा 'टीडीआर' घोटाला है। इससे भाजपा के इन सेठजी को सवा लाख करोड़ मिलेंगे। इसके अलावा मुंबई में साल्ट पैन, टोल नाका और दूध डेयरियों की जमीनें भी मिल जाएंगी। इस तरह सेठजी को सरकार गिराने और विधायकों को खरीदने के खर्च के बदले कम से कम डेढ़ लाख करोड़ मिलेंगे। इस कमाई का बड़ा हिस्सा वे महाराष्ट्र चुनाव में भी लगा रहे होंगे। भाजपा का ये पैसा उन तक दोबारा पहुंच रहा है इसलिए अगर अडानी सेठ भाजपा की राजनीतिक बैठकों में शामिल हो रहे हैं तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। साफ दिख रहा है कि अडानी सेठ सीधे तौर पर देश के कामकाज और प्रशासन में दखल दे रहे हैं। अमेरिका के 'अडानी' एलन मस्क ने अपना खजाना खाली कर दिया, ताकि ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीत सकें। अब ट्रंप ने जीतते ही एलन मस्क को अपनी वैहबिनेट में शामिल कर लिया है। यह एक सीधा व्यापार और लेन–देन है। तो चाहे वह मस्क हों या अडानी सेठ, निवेश किया गया पैसा दोगुना ही वसूल करेंगे। अडानी महाराष्ट्र में राजनीतिक बैठकों में भाग लेते हैं और उन्हें मनचाहा परिणाम मिलता है। हमारे राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ। यह सच है कि उद्योगपतियों का बढ़ता हस्तक्षेप राज्य के विकास में बाधक बनेगा, लेकिन अगर राज्य के सूत्र अडानी सेठ जैसे उद्योगपतियों के पास चले जाएं और अगर चीजें उनके मनमाफिक नहीं होंगी, तो वे सरकार को अस्थिर करने में भी संकोच नहीं करेंगे। महात्मा गांधी गुजरात से हैं। वे दक्षिण अप्रहीका से भारत लौटे। गुजरात में रहे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की कोशिश की, लेकिन गुजरात की धरती पर स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में ठंडी प्रतिक्रिया मिलते ही उन्होंने गुजरात छोड़कर महाराष्ट्र जाने का पैहसला किया। 'यहां व्यापार मंडल है। ऐसे लोगों को आजादी से कोई प्यार नहीं। वे अपने व्यापार और धंधे में ही अधिक रुचि रखते हैं।' गांधी जी को लगा कि वे गुजरात में रहकर आजादी के कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते और वे महाराष्ट्र चले गए। जहां हर चीज तराजू और पैसे में तौला जाता है, यदि सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चली जाए तो देश व राज्य एक बाजार बन जाता है और व्यापार के लिए राजनीति ही हथिया ली जाती है। अजीत पवार ने अडानी सेठ के बारे में सच बताया और २४ घंटे में मुकर गए। इसके पीछे दबाव ही है। महाराष्ट्र में सरकार गिराने के पीछे घाती शिंदे गैंग की कोई सोच और नैतिकता नहीं थी। यह सूरज की रोशनी की तरह सत्य है कि महाविकास आघाड़ी सरकार को इसलिए उखाड़ फेंका गया क्योंकि अडानी सेठ को मुंबई लूटनी है। इन अडानी सेठ का क्या करें? इसका पैहसला महाराष्ट्र की जनता को करना है।

बुलडोजर न्याय पर हथौड़ा,सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला

देश के अलग–अलग हिस्सों में शुरू हुए कथित 'बुलडोजर न्याय' के नए चलन में निहित खतरों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही इस पर प्रभावी रोक लगा दी। इस संबंध में बुधवार को आया सर्वोच्च अदालत का फैसला निश्चित रूप से सख्त फैसलों की श्रेणी में रखा जाएगा, लेकिन यह सख्ती जरूरी थी।असमंजस के हालातमामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से हो सकता है कि एक बार शुरू होने के बाद यह चलन तेजी से फैलता जा रहा था। कई राज्यों में इसे अपराधी तत्वों पर अंकुश लगाने का एक कारगर तरीका माना जाने लगा था। हालांकि इसे गलत और मान्य कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ बताने वाले भी कम नहीं थे, लेकिन न केवल आम लोगों के एक हिस्से में इसके प्रति समर्थन देखा जा रहा था बल्कि प्रशासनिक हलकों में भी इसके बचाव में कई तरह की दलीलें दी जा रही थीं। इन सबसे असमंजस के हालात बने हुए थे।एक मसला, कई पहलू

इस केस पर विचार करते हुए कोर्ट को कई सवालों से जूझना पड़ा। मसलन–कानून का पहलू तो इससे जुड़ा था ही, संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए उन अधिकारों का भी सवाल था जो उसे राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से सुरक्षा देते हैं। न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता और लोकसेवकों के प्रति आम जनों के विश्वास का प्रश्न भी इससे जुड़ा था। बारीक पड़ताल सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम पहलुओं का ध्यान रखते हुए न केवल बुलडोजर के जरिए न्याय करने की इस प्रवृत्ति को खारिज किया बल्कि उन आधारों को भी स्पष्ट किया, जिनसे इस बात की पहचान होती है कि प्रशासन ने कब अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। फैसले में कहा गया है कि जब किसी खास निर्माण को अचानक निशाना बनाया जाता है और उस तरह के अन्य निर्माणों को छुआ भी नहीं जाता, तब ऐसा लगता है कि कार्रवाई का असल मकसद किसी आरोपी को बिना मुकदमा चलाए सजा देना है।संतुलन और सख्ती खास बात यह कि शीर्ष अदालत इस तरह की कार्रवाई को गलत बताकर ही नहीं रुकी, उसने यहां तक कहा कि अगर किसी व्यक्ति का घर इस तरह से तोड़ा जाता है तो उसे फिर से बनाने का खर्च संबंधित ऑफिसरों के वेतन से काटा जाएगा। दूसरी बात यह कि अदालत ने इस फैसले की सीमाएं स्पष्ट करते हुए यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन आदि पर बने अवैध निर्माण इन निर्देशों के दायरे में नहीं आएंगे। कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती और संतुलन का जो बेहतरीन तालमेल इस फैसले में दिखाया है, वह देश में संवैधानिक मूल्यों को मजबूती देने वाली एक मिसाल के रूप में याद रखा जाएगा।

मजबूत हों स्थानीय निकाय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्थानीय निकायों की राजकोषीय स्थिति पर अध्ययन की शुरुआत करके तथा उसके निष्कर्षों को प्रकाशित करके अच्छी शुरुआत की है। नगर निकायों की वित्तीय स्थिति पर पहली ऐसी रिपोर्ट नवंबर 2022 में प्रकाशित की गई थी। उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति पर एक अध्ययन पेश किया गया। रिजर्व बैंक ने अब 2019–20 से 2023–24 के बजट अनुमानों के आधार पर नगर निकायों की वित्तीय स्थिति पर आधारित एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।अध्ययन में देश भर के 232 नगर निकायों को शामिल किया गया है। भारत में अक्सर स्थानीय निकायों पर सीमित नीतिगत ध्यान दिया जाता है। आंशिक तौर पर ऐसा इसलिए हुआ कि तुलनात्मक स्वरूप में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह भी उम्मीद की जानी चाहिए कि रिजर्व बैंक का यह अध्ययन जरूरी नीतिगत ध्यान आकृष्ट करेगा और सार्वजनिक बहस को समृद्ध करेगा। स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना अत्यधिक आवश्यक है।नगर निकायों के संदर्भ में यह बात ध्यान देने लायक है कि भारत का तेजी से शहरीकरण हो रहा है और उसे नागरिक क्षमताएं विकसित करने की आवश्यकता है। फिलहाल जो हालात हैं उनके मुताबिक भारत का करीब 60 फीसदी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) शहरी इलाकों में उत्पन्न हो रहा है और 2050 तक उसकी करीब 50 फीसदी आबादी शहरी इलाकों में रहने लगेगी।बहरहाल अधिकांश नगर निकाय इस बदलाव से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं, मोटे तौर पर ऐसा इसलिए कि उनके पास संसाधन नहीं हैं। जैसा कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट दिखाती है, नगर निकायों की राजस्व प्राप्तियां जीडीपी का केवल 0.6 फीसदी हैं। यह मामूली आंकड़ा भी चुनिंदा नगर निकायों के पक्ष में झुका हुआ है। केवल 10 नगर निकाय कुल राजस्व प्राप्तियों में 60 फीसदी के हिस्सेदार हैं।नगर निकायों का कुल व्यय जिसमें राजस्व और पूंजीगत व्यय शामिल है, वह 2023–24 के बजट अनुमान में जीडीपी के 1.3 फीसदी के बराबर था। नगर निकायों के राजस्व में संपत्ति कर, कुछ शुल्क और उपयोग शुल्क आदि शामिल होते हैं। संपत्ति कर उसके कुल राजस्व में करीब 60 फीसदी होता है।नगर निकाय केंद्र और राज्य सरकारों के अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। राज्य सरकारों, राज्यों के वित्त आयोग के अनुदान तथा अन्य जगहों से आने वाली राशि की बात करें तो 2019–20 और 2022–23 में वह इनकी राजस्व प्राप्तियों में 30 फीसदी की हिस्सेदार रही। केंद्र सरकार का हस्तांतरण उनके राजस्व में 2.5 फीसदी का हिस्सेदार रहा। नगर निकाय बाजार से भी उधारी लेते हैं, हालांकि यह उनके जीडीपी का केवल 0.05 फीसदी है।नगर निकायों की वित्तीय स्थिति दुरुस्त करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने लायक बनाना होगा। अधिकांश विकसित और विकासशील देशों में सामान्य सरकारी राजस्व और व्यय में स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी बहुत अधिक है। राजकोषीय शक्तियों में इजाफा तथा सामाजिक जवाबदेही, आर्थिक और सामाजिक परिणामों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाताओं के लिए यह हमेशा आसान होता है कि वे अपने स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराएं।नगर निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न स्तरों पर हस्तक्षेप की जरूरत होगी। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि निकायों को खुद अपना राजस्व बढ़ाने पर काम करना होगा। उदाहरण के लिए संपत्ति कर में सुधार की जरूरत है क्योंकि संपत्तियों का मूल्यांकन बढ़ रहा है। कराधान का दायरा और गुंजाइश बढ़ाने के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल करना होगा। इन निकायों को उपयोगकर्ता शुल्क को भी समुचित बनाना होगा।कुल मिलाकर सरकार के उच्च स्तरों पर निर्भरता कम करने की जरूरत है जिससे राजस्व के बारे में एक अनुमान लग सकेगा। एक संभावना यह है कि जरूरी कानूनी बदलावों के बाद स्थानीय निकायों को वस्तु एवं सेवा कर में हिस्सा दिया जाए। इससे न केवल इन निकायों को विकास परियोजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी बल्कि वे अधिक अनुकूल शर्तों पर ऋण भी जुटा सकेंगे। कुछ नगर निकायों ने बॉन्ड बाजार का रुख भी किया है। अब वक्त आ गया है कि भारत स्थानीय निकायों की स्थिति और भूमिका पर नए सिरे से विचार करे।

बुलडोजर 'न्यायाधीश' नहीं

बुलडोजर न तो न्याय है और न ही 'न्यायाधीश' का कोई पर्याय है। बुलडोजर की कार्रवाई और किसी के घर को 'मलबा' करने की जबरन कवायद पर सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला दिया है, वह मील–पत्थर, ऐतिहासिक और दूरदर्शी है। सर्वोच्च अदालत ने कुछ दिशा–निर्देश तय किए हैं, जो देश भर में लागू होंगे। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'घर' को भी एक अधिकार माना गया है, लिहाजा किसी आरोपित या सजायाफ्ता व्यक्ति के घर को ध्वस्त करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन, हनन है। अपराध–शास्त्र का बुनियादी सिद्धांत यह है कि जिसने अपराध किया है, उसी को सजा दी जाए, लेकिन देश के आधा दर्जन राज्यों में इस सिद्धांत की अनदेखी की जाती रही है। बुलडोजर को सजा देने अथवा राजनीतिक खुन्नस का ऐसा हथियार बनाया गया है कि घर ढहाने से कथित अपराधी का पूरा परिवार प्रभावित होता है। वे बेघर हो गए। मुआवजे के तौर पर सरकार ने जिन आवासों की पेशकश की, वे 5–7 परिजनों के लिए अपर्याप्त थे। सरकारों ने बुलडोजर की कार्रवाई को ही अपना कानून तय कर लिया, लिहाजा उसे 'बुलडोजर न्याय' का नाम दिया गया। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'बुलडोजर बाबा' कहा गया और मप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 'बुलडोजर मामा' के नाम से लोकप्रिय हुए। बुलडोजर को अपराधियों में सरकारी खौफ का विकल्प बना दिया गया। कथित माफिया, डॉन, गुंडों के अवैध निर्माण 'मलबा' किए गए। इनमें अतीक अहमद, मुफ्तार अंसारी, आजम खान सरीखों के नाम लिए जा सकते हैं, जो बार–बार जनप्रतिनिधि भी चुने गए और विधानसभा, संसद के सदस्य तक बनते रहे। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ उप्र के मुख्यमंत्री चुने गए, तब उन्होंने ऐलान किया था कि अपराधियों, माफिया किस्म के लोगों के अवैध निर्माण ढहाए जाएंगे। यह कार्रवाई एक कानूनी सीमा के दायरे में ही की जा सकती है और इसकी एक निश्चित कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए।बुलडोजर कार्रवाई को कोई भी सरकार 'प्रतिशोध' का पर्याय नहीं बना सकती, लिहाजा अब जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की न्यायिक पीठ को फैसला देना पड़ा है कि कार्यपालिका (यानी सरकार और नौकरशाही) 'न्यायाधीश' नहीं हो सकती। अब किसी अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई करनी होगी, तो सरकार को साबित करना होगा कि अमुक निर्माण 'अवैध' किन आधारों पर है? क्या उसे ध्वस्त करना ही 'अंतिम विकल्प' है? क्या जुर्माना वसूल कर उस अवैध निर्माण को 'नियमित' नहीं किया जा सकता? न्यायिक पीठ का कहना है–आम नागरिक के लिए अपना घर बनाना सालों की मेहनत और सपनों का नतीजा है।दांत क्या थम जाएंगे? आश्रय के अधिकार पर तानाशाही नहीं की जा सकती।

बुलडोजर कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के अहम दिशा–निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर दिशा–निर्देश जारी करके यह सुनिश्चित करने का काम किया कि अतिक्रमण, अवैध निर्माण के साथ–साथ अपराध के खिलाफ मनमानी कार्रवाई न होने पाए। ऐसा किया जाना आवश्यक था, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई अपराध में लिप्त तत्वों के खिलाफ भी होती थी और इस आधार पर होती थी कि उन्होंने अपना मकान, दुकान या अन्य कोई इमारत अवैध रूप से बना रखी है। शासन–प्रशासन को ऐसी कार्रवाई करने में इसलिए आसानी होती थी, क्योंकि प्रायः लोग अपने भवनों का निर्माण स्वीकृत मानचित्र या तय मानकों के हिसाब से नहीं कराते।बुलडोजर कार्रवाई को इसलिए जनता का समर्थन मिलता था, क्योंकि उसकी यह आकांक्षा रहती है कि अपराधी तत्वों को यथाशीघ्र दंड मिले। इसी कारण बुलडोजर कार्रवाई की सराहना होती थी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस तरह की कार्रवाई में संदिग्ध अपराधी–अभियुक्त का घर–दुकान ध्वस्त होने से उसके स्वजन भी सजा पाते थे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी आरोपित की सजा उसके परिवार वालों को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जो दिशानिर्देश जारी किए, उनके आधार पर इस नतीजे पर भी नहीं पहुंचा जाना चाहिए कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का रास्ता बंद होने जा रहा है।सुप्रीम कोर्ट के दिशा–निर्देशों से यह स्पष्ट है कि अनधिकृत निर्माण के खिलाफ नोटिस भेजने और मामले की सुनवाई करने के बाद बुलडोजर कार्रवाई संभव है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्याख्या इस रूप में भी की जा रही है कि इससे माफिया तत्वों और पेशेवर अपराधियों पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। देखना है कि ऐसा होता है या नहीं? जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर अतिक्रमण हटाने और जमीनों पर कब्जे रोकने पर नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह अपराधी तत्वों का दुस्साहस भी नहीं बढ़ना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि बिना फैसले किसी को दोषी न माना जाए और अपराधी को दंड देना अदालत का काम है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या अदालतें यह काम सही तरह से कर पा रही हैं? अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट पर इस प्रश्न पर भी गौर करता, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि अपराधी और माफिया तत्वों को उनके किए की सजा मुश्किल से ही मिलती है। मिलती भी है, तो बहुत विलंब से। बाहुबली, धनबली किस्म के या फिर राजनीतिक असर वाले अपराधी तत्वों के मामलों में यही अधिक देखने को मिलता है कि वे अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों को लंबा खींचने में सफल हो जाते हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि संगीन अपराध में लिप्त तत्वों को भी शीघ्र सजा नहीं मिल पाती। इसी कारण लोग बुलडोजर कार्रवाई को न्याय की संज्ञा देते हैं। अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट यह देख पाता कि बुलडोजर कार्रवाई न्याय में देरी की उपज है।

जननायक सम्राट

हिन्दी साप्ताहिक

मालिक,मुद्रक, प्रकाशक आरती वर्मा द्वारा आशु प्रिंटिंगप्रेस,अचलताल अलीगढ़ से मुद्रितकराकर . कार्यालय सरोज नगर गली नम्बर 5,अलीगढ़ से प्रकाशित

सम्पादक–अमित कुमार वर्मा

सभी विवाद का न्याय क्षेत्र जनपद अलीगढ़ न्यायलय ही होगा

आवश्यकता है

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र जननायक सम्राट के लिए जिला ब्यूरो चीफमंडल ब्यूरो चीफ ब्लाक ,ब्यूरो संवाददाता की आवश्यकता है।

सम्पर्क करें -

अमित कुमार वर्मा -संपादक

मो:-8218049162,8273402499